आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए दृष्टिकोण पत्र

*388. श्री विश्वासराव रामराव पाटिल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिये दृष्टिकोण पत्र का अध्ययन करने के लिये हाल ही में योजना आयोग की बैठक आयोजित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसमें दृष्टिकोण पत्र का अनुमोदन किया गया था; और

(ग) इसे मंजूरी के लिये राष्ट्रीय विकास परिषद को कब तक प्रस्तुत कर दिया जायेगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेश गोवर्धन) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) दृष्टि कोण-पत्र का मसौदा केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है तथा उसे राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष, उसकी 18 तथा 19 जून, 1990 को होने वाली बैठक में रखने का प्रस्ताव है।

Approval to power and irrigation projects of Madhya Pradesh

*389. SHRI AJIT P. K. JOGI:
SHRI\CHHOTUBHAI PATEL:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether some proposals for power and irrigation projects in Madhya Pradesh are awaiting the approval of the Planning Commission;

(b) if so, the number of such projects sent by Madhya Pradesh Government to the Planning Commission till the end of February, 1990;

(c) the number of projects approved by the Planning Commission for inclusion in the State's Annual Plan of 1990-91 and also in the Eighth Five Year Plan; and

(d) the steps taken by Government to give clearance to those projects ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRYOF PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI BHAGEY GOBARDHAN): (a) No power or irrigation project proposed to be executed in Madhya Pradesh is pending with Planning Commission for investment clearance.

(b) to (d) Do not arise.

शिक्षा के लिए दी गई केन्द्रीय निधियों का राज्यों द्वारा अपयोजित किया जाना

*390. डा. जिनेन्द्र कुमार जैन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ वर्षों के दौरान, अनेक राज्य सरकारों ने शिक्षा के प्रसार व निरक्षरता दूर करने के लिये बनाई गई विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत दी गई राशि अन्य मदों के लिये अपयोजित तथा व्यय कर दी ;

(ख) यदि हां, तो किस-किस राज्य सरकार ने, किस वर्ष में, कितनी राशि का दुरुपयोग किया ; और

(ग) क्या सरकार ने भविष्य में निधियों के इस प्रकार के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिये कोई कदम उठाये हैं ; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?